



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी 2020—माघ 4, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

No. A-72

Jabalpur, the 10th January 2020

In exercise of the powers conferred by Articles 225 of the Constitution of India, section 54 of the States Reorganisation Act, 1956, clauses 27 and 28 of the Letters Patent, the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the High Court of Madhya Pradesh Rules, 2008, which shall come into force from the date of notification in the Madhya Pradesh Official Gazette (Extra-ordinary).

Amendment

1. In sub-rule (1) of rule 1 of chapter V,-

- (i) Clause (r) shall be deleted.
- (ii) For Clause (u), the following clause shall be substituted, namely:-
“(u) to decide application given on behalf of the Party for refund of Court fee. If the Registrar is satisfied that any Court fee has been paid in excess or inadvertently, he may issue a Certificate to refund and shall communicate the same to the concerned Treasury Officer;”

2. In sub-rule (7) of rule 2 of chapter X,-

- (i) In clause (b), between the words “side of a” and the words “ledger paper”, the words “light green” shall be inserted.
- (ii) After clause (b), the following clause shall be added, namely;
“(c) It shall be printed using double space, font size of 14 and font face Arial / Times New Roman. Copy for opposite party be on white durable paper;”
- (iii) Clause (c) shall be renumbered as clause (d).

3. In chapter X,-

- (i) In sub-rule (1) of rule 23, between the words “Petition for” and the words “a direction” the words and comma “quashing a criminal case,” shall be inserted.
- (ii) After rule 15, the following rule shall be added, namely:-
“15A. A Memorandum of Arbitration Case under Section 11 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall be so far as may be in Format No. 6A.”

4. After Format No.6, the following format shall be added, namely;

**Format No. 6A
(Chapter X, Rule 15A)**

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR/BENCH AT INDORE /
BENCH AT GWALIOR**

Arbitration Case No. /20.....

Cause Title

Applicant(s) : The name [Company/Institution/Firm/
Person(s)], age
....., father/husband's name,
occupation....., complete
address....., fax number with
S.T.D. Code And E-mail
address....., if any; of each
Applicant

Vs.

Non-Applicant(s) : The name [Company/Institution/Firm/
Person(s)], age,
father/husband's name,
occupation, complete
address, fax number with
S.T.D. Code and E-mail address
....., if any; of each Non-
Applicant

(An application under Section 11 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996)

The Applicant(s) beg to submit for appointment of Arbitrator(s) on the following facts and grounds:-

1. There is an Arbitration Agreement dated between Applicant & Non-Applicant.
2. Whether original/certified copy of the agreement is filed - if not, reason therefor:
3. The date on which a request for referring the dispute to the Arbitration has been made by the Applicant to the Non-Applicant.
4. The description with date of reply of Non-Applicant, if any:
5. Details of remedies exhausted:
 - (a)
 - (b)
 - (c)

The Applicant declares that he has taken all necessary steps for appointment of an Arbitrator(s).

6. Delay, if any, in filing the application and explanation therefor:
(State exact period within which the application is filed after expiry of statutory period for appointment of Arbitrator(s), if any)
7. Facts of the case:
(Give a concise statement of facts in chronological order in separate paragraphs)
8. Grounds urged:
(Separately state the grounds on which the relief(s) is/are claimed)
9. Specify whether any application under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 was previously instituted before any Court, the status or result thereof along with copy of the order, if any.

OR

A declaration that no proceeding on the same subject matter has been previously instituted before any Court.

10. Relief Prayed for :
(Specify below the relief prayed for)

Place:

Date:

Name:

Signature :

of Advocate for Applicants (s)

राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल.

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

एफ 5-01-2020-1-पचपन

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2020

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन 2001) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय शिक्षा (सह-चिकित्सीय संस्थाओं की स्थापना के लिए मानक तथा मार्गदर्शक) नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4 में,—

(1) उपनियम (ड) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थातः—

“(ड) (एक) आवेदक के स्वामित्व/प्रबंधन में कम से कम 100 बिस्तरों का (स्नाकोत्तर उपाधि, पत्रोपाधि एवं प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट) पाठ्यक्रमों के लिए) 1:3 (एक बिस्तर पर तीन छात्र/छात्राएँ) के औसत अनुपात के आधार पर, आवश्यक अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ एक अस्पताल है और परिषद् द्वारा यथाविहित शिक्षण संस्था में विकसित होने की क्षमता है एवं जो प्रस्तावित संस्था के समीप स्थित है।

परन्तु संस्था छात्रों को आवागमन हेतु परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती है तो संस्था से अस्पताल की दूरी 15 कि.मी. होने पर भी संस्था के मान्यता संबंधी आवेदन पर विचार किया जा सकेगा।

(दो) न्यूनतम 100 बिस्तरों के अस्पताल की व्यवस्था होने पर अनुज्ञा के लिए आवेदन पर विचार किया जा सकेगा और समाधान के पश्चात् अनुज्ञा मंजूर की जा सकेगी।

(तीन) ऐसी संस्था जो जिला स्तर एवं या ब्लॉक स्तर पर सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम संचालित करने का आशय रखती है और जिसने न्यूनतम 100 बिस्तरीय (1:3 एक बिस्तर पर तीन छात्र/छात्राएँ) शासकीय चिकित्सालय की संबद्धता प्राप्त कर ली है तो अनुज्ञा के लिए आवेदन पर, विचार किया जा सकेगा :-

(क) शासकीय चिकित्सालय से अनुज्ञा/संबद्धता की दशा में विद्यमान शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी;

(ख) समान वरिष्ठता होने की स्थिति में, प्रस्तावित शिक्षण संस्था की अधोसंरचना, अन्य सुविधाएं एवं पूर्व वर्षों के परीक्षा परिणाम निर्णायक कारक होंगे।"

(2) उप- नियम (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(ज) आवेदक, एक से तीन पाठ्यक्रमों के लिए तीन लाख रुपये, एक से दस पाठ्यक्रमों के लिए पाँच लाख रुपये और दस से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए पाँच लाख रुपये के अतिरिक्त समस्त विषयों में प्रत्येक अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिए दो लाख की दर से, परिषद् के पक्ष में एक सावधि जमा, परिषद् द्वारा निर्धारित अधोसंरचनात्मक, शिक्षण और अन्य मानकों की पूर्ति के लिए प्रस्तुत करेगा। यदि परिषद् का यह मत है कि संस्था नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई सावधि जमा, परिषद् द्वारा समपहृत हो जाएगी।"

2. नियम 5 में, प्रारंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“आवेदक द्वारा, पात्रता मानदंड और अर्हकारी मानदंड की पूर्ति के अधीन रहते हुए एक नया सह-चिकित्सीय शिक्षा संस्था स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से निम्नलिखित तीन भागों में प्रस्तुत किया जाएगा:—”

3. नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“6. आवेदन फीस.—

(1) मान्यता हेतु निर्धारित अंतिम तिथि को या उससे पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने की दशा में, आवेदन फीस, ऑनलाइन मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् भोपाल के पक्ष में, इंटरनेट बैंकिंग, आरटीजीएस, आईएमपीएस या एनईएफटी के माध्यम से, प्रति पाठ्यक्रम निम्नानुसार भुगतान की जाएगी —

(एक) आठ हजार पाँच सौ रुपये मात्र	स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम के लिए
(दो) तैंतीस हजार रुपये मात्र	स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम के लिए
(तीन) बाईस हजार रुपये मात्र	पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम के लिए
(चार) सोलह हजार पाँच सौ रुपये मात्र	प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट) पाठ्यक्रम के लिए

(2) उक्त उल्लिखित राशि में प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

(3) मान्यता के लिए देरी से आवेदन करने की दशा में, उस पर अध्यक्ष, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् विचार किया जाएगा, यदि उप नियम (1) के अधीन विहित आवेदन फीस के साथ निम्नानुसार अतिरिक्त फीस जमा की जाती है :—

1. निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन कोई अतिरिक्त फीस नहीं
 2. निर्धारित अंतिम तिथि से 15 दिवस तक विहित फीस के 5 प्रतिशत के बराबर राशि
 3. निर्धारित अंतिम तिथि से 30 दिवस तक विहित फीस के 10 प्रतिशत के बराबर राशि
- (4) मान्यता हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से 30 दिवस की कालावधि के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (5) इस फीस में तकनीकी सुरक्षा, आकस्मिक व्यय तथा परीक्षा के निरीक्षण और प्रत्येक व्यावसायिक परीक्षा की समाप्ति पर मूल्यांकन के रजिस्ट्रीकरण के लिये फीस सम्मिलित है। यदि संस्था का निरीक्षण, परिषद्/ राज्य सरकार द्वारा निदेशित निरीक्षण समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व नहीं किया जाता है तो संस्था के अनुरोध पर संस्था द्वारा जमा की गई फीस में से 10 प्रतिशत कटौती करने के पश्चात् फीस की शेष रकम प्रतिदाय कर दी जाएगी:

परंतु किसी तकनीकी कारण से निरीक्षण नहीं किया जाता है या आवेदक ऐसा निरीक्षण न किए जाने की वांछा करता है तो संस्था के लिखित अनुरोध पर संस्था द्वारा जमा की गई फीस में से नीचे यथा विहित राशि का कटौती करने के पश्चात् फीस की शेष रकम के प्रतिदाय पर विचार किया जाएगा:-

- (एक) आवेदन के दिन से 30 दिन के भीतर 10 प्रतिशत राशि काटौती की जाएगी अनुरोध किये जाने पर
- (दो) आवेदन के दिन से 180 दिन के भीतर 25 प्रतिशत राशि काटौती की जाएगी अनुरोध किये जाने पर

परन्तु प्रतिदाय के लिए किसी आवेदन पर 180 दिवस के पश्चात् विचार नहीं किया जाएगा।”

4. नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

9. मूल्यांकन.- (1) परिषद् प्रथमतः आवेदन के 'भाग-क' को प्रस्तावित स्थल पर सह-चिकित्सीय शैक्षणिक संस्था स्थापित करने की वांछनीयता और प्रथम दृष्टया साध्यता का मूल्यांकन करेगी और स्कीम के लिए आवश्यक संसाधन तथा अधोसंरचना उपलब्ध कराने की आवेदक की सामर्थ्य का भी मूल्यांकन करेगी। परिषद्, आवेदन-पत्र के प्रत्येक भाग का मूल्यांकन करते समय, जैसा कि वह आवश्यक समझे, आवेदक से और भी जानकारी/ स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज की मांग कर सकेगी। उसके पश्चात् उपनियम (2) के अनुसार गठित समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर मान्यता प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

(2) सत्यापन हेतु समिति निम्न से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. कलक्टर या उसका प्रतिनिधि जो अपर कलक्टर/ संयुक्त कलक्टर के पद से नीचे का न हो | अध्यक्ष-
नोडल अधिकारी |
| 2. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग या उसका प्रतिनिधि | सदस्य |
| 3. चिकित्सा महाविद्यालय के विषय-विशेषज्ञ (केवल उन स्थानों हेतु जहां चिकित्सा महाविद्यालय हो) / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या उसका प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4. जिला आयुष अधिकारी (केवल उन संस्थाओं हेतु जिनके द्वारा आयुष से संबंधी पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन किया गया हो) | सदस्य” |

F 5-01-2010-1-LV

In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Paramedical Education (Norms and guidelines for Establishment of Paramedical Institutions) Rules, 2007, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In rule 4,-

(1) for sub-rule (e), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(e) (i) That the applicant owns and manages a hospital of not less than 100 beds (for post-graduate, graduate degree, diploma and certificate courses) on the basis of average 1:3 ratio (three students on one bed) with necessary infrastructural facilities and capable for being developed into teaching institution as prescribed by Parishad and which is in the vicinity of the proposed institute:

Provided that the institute provides

students the facility for transportation, the application related to the recognition of the institution may be considered even if distance of the hospital from institute is up to 15 km.

That on availability of a hospital having minimum of 100 beds, the application for permission may be considered and after being satisfied, permission may be granted.

That those institutions who intend to conduct Para-Medical courses at any district and or block level and has obtained affiliation with a Government Hospital having minimum 100 beds (average 1: 3 ratio i.e three students on one bed), then the application for permission shall be considered as per the following: -

- (a) In case of the permission /affiliation with government hospital, priority shall be given to the courses of the existing educational institutions;
- (b) In case of equal seniority, the infrastructure and facilities of the proposed educational institution and the results of previous year's examinations, shall be the decisive factor."

- (2) for sub-rule (j) the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(j) That the Applicant shall submit a fixed deposit of rupees three lakh for one to three courses, rupees five lakh for one to ten courses and in case of more than ten courses, in addition to rupees five lakh amount at the rate of two lakh for each additional course for all subjects in favour of the parishad for fulfillment of infrastructural, teaching and other standard norms fixed by the parishad. If the parishad is of the opinion that the institution is not working as per rules then the fixed deposit submitted by the institution shall be forfeited by the Parishad. "

2. In rule 5, for opening Para, the following para shall be substituted, namely:-

"Subject to the fulfillment of the eligibility criteria and qualifying criteria, the application for permission to establish Para-Medical Educational Institute shall be submitted online by the applicant in the following three part:-"

3. For rule 6, the following rule shall be substituted, namely:-

"6. Application fees.-

- (1) In case of submitting application on or prior to the last date prescribed for application of recognition, application fees per course will be deposited in favour

of Madhya Pradesh Paramedical Council Bhopal, on line by Internet Banking, RTGS, IMPS or NEFT as per the following.-

- | | | |
|-------|--|---------------------------------|
| (i) | 60500/- (Sixty thousand five hundred rupees only) | for post-graduate degree course |
| (ii) | 33000/- (thirty three thousand rupees only) | for graduate degree course |
| (iii) | 22000/ (Twenty-two thousand rupees only) | for the diploma course |
| (iv) | 16500/-(Sixteen thousand five hundred rupees only) | for the certificate course |

(2) An escalation of 6% shall be made every year in the above mentioned amounts.

(3) In case of late submission of application for recognition, same shall be considered after approval of Chairman, MP Paramedical Council if along with the application fees prescribed in sub-rule (1), an additional fee is remitted as per the following.-

- | | | |
|-------|---|---|
| (i) | Application by the prescribed last date | No additional fees shall apply. |
| (ii) | Up to 15 days from the prescribed last date | An amount equal to 5 percent of prescribed fees. |
| (iii) | Up to 30 days from the prescribed last date | An amount equal to 10 percent of prescribed fees. |

(4) No application shall be entertained after a period of 30 days from the last date prescribed for recognition.

- (5) The fee is inclusive of registration, technical security, contingency expenditure and inspection / evaluation of examination at the end of each professional examination. If the inspection of the institution is not made before commencement of academic session by the Inspection Committee directed by the Council / State Government, then on the request of the institution after deduction of 10 percent remaining amount shall be refunded to the institute:

Provided that for any technical reason inspection is not made or the applicant wishes not to carry out such inspection then on the request of the institution in writing, after deducting the amount as prescribed below from the fees deposited by the institution, the remaining amount of fees shall be considered to be refunded: -

- | | | |
|------|---|--------------------------------------|
| (i) | On being requested within 30 days of application | 10 percent amount shall be deducted |
| (ii) | On being requested within 180 days of application | 25 percent amount shall be deducted. |

Provided that no application for refund shall be considered after 180 days.

For rule 9, the following rule shall be substituted, namely:-

"9. Evaluation.-

- (1) The parishad shall evaluate Part-A of the application in the first instance the desirability and prima facie feasibility of setting up the Paramedical Educational Institution at the proposed location and shall also evaluate the capability of the applicant to provide the necessary sources and infrastructure for the scheme. The parishad while evaluating each part of the application may seek further information, clarification or additional documents from the applicant as considered necessary. Thereafter physical verification shall be carried out by the committee constituted per sub-rule (2). On the report submitted by the said committee, grant of recognition shall be considered.
- (2) The committee for verification shall comprise of the following, namely:-

1.	Collector or his representative who is not below the rank of Additional Collector / Joint Collector	Chairman-Nodal Officer
2.	Executive Engineer, Public Works Deptt. or his representative	Member
3.	Subject Specialist of Medical College (for those places only where Medical College exists) / Chief Medical and Health Officer or his representative	Member
4.	District AYUSH Officer (Only for those institutions that have applied for AYUSH related courses)	Member. "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोमेश मिश्र, उपसचिव.